

दिनांक-23 जुलाई 2024

7:20 AM

पहले मुख्य समाचार।

- केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट।
- लोकसभा में पूरक प्रश्नों के जवाब में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा सात वर्षों में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया।
- मुख्यमंत्री ने की वाराणसी और आजमगढ़ के विकास कार्यों की समीक्षा। फोन न उठाने वाले बिजली अभियंताओं पर दिया कार्रवाई का निर्देश।
- सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर लगायी अंतरिम रोक। सरकार से मांगा जवाब।

एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फ़ैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले पांच वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

यह बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और यह बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकरके हम कल देश के सामने आएंगे।

संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार तेइस-चौबीस पेश किया। इसके अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है।

केन्द्र सरकार दो हजार तेइस के राजकोषीय घाटे को छह दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर दो हजार पच्चीस में सकल घरेलू उत्पाद के पांच दशमलव छह प्रतिशत तक ले आई है। वित्त वर्ष दो हजार चौबीस-पच्चीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर साढ़े छह से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों में देश में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार, नीट-यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छिपा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अपनी स्थापना के बाद से दो सौ चालीस परीक्षाएं आयोजित की हैं। इनमें साढ़े चार करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। श्री प्रधान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस बयान को निंदनीय बताया, जिसमें उन्होंने देश की परीक्षा प्रणाली की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर श्री प्रधान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं और अपने भविष्य को लेकर चिन्तित हैं।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में कल नीट-यूजी पेपर लीक मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट ने एक सवाल के दो सही विकल्प के मामले में आईआईटी दिल्ली के निदेशक से तीन सदस्यीय समिति गठित कर के आज दोपहर बारह बजे तक सही उत्तर पर राय देने के लिए कहा है। इस मामले में आज सुनवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आजमगढ़ और वाराणसी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को समय से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के फोन न उठाने की शिकायत पर उन्होंने नाराजगी जतायी और ऐसे अवर अभियंता, सहायक अभियंता और एसडीओ को चिन्हित कर के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये। विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाये और नोडल अधिकारी नियुक्त कर के हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट ली जाये। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर सतर्क रहने और तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम सोलह घंटे बिजली दी जाय। अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना कर क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से इस पर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई छब्बीस जुलाई को तय की है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स सहित कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य के डीजीपी और मुजफ्फरनगर के एसएसपी के अलावा उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नीस जुलाई को एक आदेश जारी करके कांवड़ यात्रा के रूट के सभी दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों के आगे अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चित्रकूट में कल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार विष मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक होने के साथ-साथ कम वर्षा में तैयार होते हैं, इनमें प्रसंस्करण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से हलर मशीन लगायी जायेगी।

उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है जिसे प्राप्त कर महिलाएं स्वावलंबी बनेगी एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। श्री शाही ने खेती में इस्तेमाल की जा रही अत्यधिक यूरिया, डीएपी और रसायनों के नुकसान की चर्चा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उगाए गये विषमुक्त खाद्यान्न जो कि स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए आवश्यक है, किसान उसे ही उगायें।

पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम समेत वाराणसी के कैथी स्थित मार्कण्डेय महादेव मंदिर, सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव, रायबरेली के मोहनेश्वर धाम मंदिर, कानपुर के बाबा नागेश्वर मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर, गोरखपुर के महादेव झारखण्डी, मुंजेश्वरनाथ और देवरिया के दुग्धेश्वरनाथ सहित अन्य मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया।

अमरोहा में कल कांवड़ यात्रा के दौरान दो हादसों में चार कांवड़ियों की मौत हो गई और बीस से अधिक कांवड़िए घायल हो गए। ये सभी कांवड़िए ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिससे दो कांवड़ियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। उधर, इसी थाना क्षेत्र में अतरासी टोल प्लाजा के निकट मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दी जिससे दो कांवड़ियों की मौत हो गई और दो कांवड़िए घायल हो गए। इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर मोटरसाइकिल आपस में टकराने से चौदह कांवड़िये घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मृतक मुरादाबाद जिले के रहने वाले थे।

कोविड महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर तैनात किये गये बाइस सौ कर्मचारियों को निकाला नहीं जायेगा। उन्हें एनएचएम, उत्तर प्रदेश के दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समायोजित किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर एनएचएम की मिशन निदेशक डॉक्टर पिकी जोवेल की ओर से इस सम्बन्ध में कल आदेश जारी कर दिये गये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम अन्न सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन मंदिर के भोजनालय में बने भोजन को हॉस्पिटलों और संस्कृत विद्यालयों में पहुंचाएगी।
